POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

बजट

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अप्रेल, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राज्य विधान सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रखा। इस बार बजट में चुनावी साल होने और फिर से सरकार बनाने की चाह में किसानों को खुश करने के लिए मुफ्त बीज और बिजली देने जैसी कई घोषणाएं की गई है।

इसी तरह आमजन की सेहत के लिए भी मतदाताओं की नब्ज टटोलते हुए चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर लोगों को आस बंधाई है। बजट मदों के तहत करीब-करीब पूर्व में जारी सभी योजनाओं में भी धन राशि बढ़ाते हुए उन्होंने दिल खोलकर राहतें बांटी। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ही सफाई देते हुए कहा भी है कि यह बजट चुनावी नहीं है। पिछले चार सालों से जीरो टैक्स वाला बजट दे रहा हूं....। इस पर निर्णय अब चुनाव में मतदाताओं को करना है।

अमूमन देखा गया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए वह अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में इसी तरह राहतों का खजाना खोलती रही हैं और मतदाताओं के मानस को टटोलती भी रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जिन कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्षरत रहते हुए अपने कार्यकाल को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं, यह उनके राजनीतिक अनुभव को दर्शाता है।

मेरा मानना रहा है कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने, बजट घाटे को कम करने और वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ नौकरशाही को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है।

जितना वित्तीय संसाधनों को समय पर जुटाना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उन्हें दक्षता के साथ निर्धारित समय पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

खेती और किसानों के लिए सौगातों की झड़ी

इस बार प्रदेश के बजट में खेती और किसानों के फायदे के लिए 1,84,311.57 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। कृषि कनेक्शन में अब 2000 यूनिट तक का उपभोग करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। पहले यह सीमा 1000 यूनिट थी। बजट में किसानों को 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित करने का प्रावधान रखा गया है। कृषि कल्याण कोष की राशि को बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले यह राशि 5 हजार करोड़ थी।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर 13,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर सर्टिफिकेशन यूनिट व टेस्टिग लैब स्थापित होंगी। साथ ही 50 हजार किसानों को 5 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा भी बजट में है। सरकार के पिछले बजट के 11 मिशन में अब 12वां मिशन और जोड़ा गया है। इसके तहत युवाओं के लिए 'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन' की स्थापना होगी, यह एक सराहनीय कदम है। इससे युवा वर्ग का कृषि व इससे संबंधित व्यवसायों की ओर रुझान बढ़ेगा। बजट में पांच जिलों में नए कृषि महाविद्यालय तथा बस्सी व सीकर जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। पशुपालकों को लंपी बीमारी से मरी गायों का 40 हजार रुपए प्रति गाय के हिसाब से मुआवजा देने, पशु मित्र योजना और कामधेनु योजना लागू करने जैसे कई प्रस्ताव बजट में हैं। जिनसे किसान और पशुपालक लाभान्वित होंगे।

नब्ज़ पर रखा हाथ, चिरंजीवी देगी साथ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में मुफ्त की योजनाओं को ज्यादा अहमियत दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। दुर्घटना बीमा राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी अब चिरंजीवी बीमा का लाभ निःशुल्क मिलेगा। निःशुल्क जांच योजना की गुणवत्ता के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। बचे हुए तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और खुलने पर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। बजट में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल युनिवर्सिटी तथा जयपुर में एसएमएस व आरयूएचएस में सुविधाओं का विस्तार करने जैसे कई प्रस्ताव बजट में हैं।

आयुर्वेद चिकित्सालयों में भी सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का वादा बजट में किया गया है। उप जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र व सेटेलाइट अस्पताल खोलने के साथ ही क्रमोन्नत किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले बजट में की गई सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज मुफ्त करने की घोषणा काफी लाभदायक सिद्ध हुई है। इस बार बजट में स्वास्थ्य को केंद्रित करते हुए जनहित में और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2023

जरूरी है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना

उपभोक्ता संस्था 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में यह उभर कर सामने आया कि आज अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं विश्व स्तर पर गहरे होते जा रहे ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, जिसका कमजोर उपभोक्ताओं पर खासतौर पर अनकहा प्रभाव पड़ रहा है।

संगोष्ठी में 'कट्स' के पॉलिसी एनालिस्ट आकाश शर्मा ने बताया कि आज के समय में स्वच्छ ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। ऊर्जा की हर क्षेत्र में खपत बढ़ती जा रही है। ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न स्त्रोतों से हमारा पर्यावरण प्रदूषण तो लगातार बढ़ ही रहा है साथ ही संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इन सबसे निजात पाने के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक उपभोक्ताओं की पहुंच जरूरी है। यह विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभाने में सहायक होगी।

संगोष्ठी के प्रारंभ में 'कट्स' के सह निदेशक दीपक सक्सेना ने 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' मनाने, उसके मुख्य उद्देश्यों, उपभोक्ता अधिकारों और सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' 2023 का विषय 'स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' है। संगोष्ठी में मौजूद प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की अहमियत पर अपने विचार रखे।

शिक्षा के द्वार, करेंगे सपने साकार

अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के साथ बालकों के लिए भी 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। बजट में अब छात्र एवं छात्राओं के लिए रोडवेज बसों में उच्च शिक्षा के लिए भी मुफ्त यात्रा की सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 26 राजकीय महाविद्यालय, 20 महिला महाविद्यालय खोले जाएंगे।

इसके अलावा बजट में 11 नए आईटीआई और 7 संचालित आईटीआई को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाने, पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नई ब्रांच शुरू करने और रिसर्च को बढ़ावा देने जैसी कई घोषणाएं हैं। 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने, 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने और 300 विद्यालयों में नए विषय चालू करने से प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी। स्कूलों में मिड- डे -मील और प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने से बच्चों को समुचित पोषण मिल सकेगा।

मुफ्त की बिजली व छूट से होगा फायदा

बजट अनुसार कृषि कनेक्शन में अब 2000 यूनिट तक का उपभोग करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। अब 100 यूनिट का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का भी विद्युत शुल्क शून्य हो जाएगा। बाकी घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में छूट का प्रावधान है। लेकिन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट अरबन सेस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी। इसमें सौ यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ता हैं, फिक्स चार्ज अलग है।

राज्य में 1.54 करोड़ उपभोक्ताओं में से 1.19 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले एक करोड़ चार लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इनके सालाना करीब 5200 करोड़ रुपए के बिजली बिल भुगतान सरकार वहन करेगी। जबकि, बाकी 15 लाख घरेलू उपभोक्ता को हर साल बिल में 1800 करोड रुपए की छूट मिलती रहेगी। यह छूट 300 से 750 रुपए तक है। इसमें 300 यूनिट ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले भी शामिल हैं। जिन्हें स्लेबवार बिल में छूट दी जाएगी।

महिलाओं को दी गई है कई सहूलियतें

बजट में महिलाओं को कई तरह की सहूलियतें देकर खुश करने का प्रयास किया गया है। महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले एक लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने तथा पांच लाख नए परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़े जाने का वादा सराहनीय है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का ऋण प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं 8 हजार नए आंगनबाड़ी और 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देख-भाल के लिए 500 प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर शुरू करने, संभाग मुख्यालयों पर 100 व जिला मुख्यालयों पर 50 इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल खोलने, रोडवेज बसों में दी जा रही छूट को बढ़ाकर 50 फीसदी करने, सामूहिक विवाह अनुदान राशि बढ़ाने जैसी कई घोषणाएं महिला वर्ग को लाभान्वित करेंगी।

आधारभूत ढांचा हो मजबूत, खोला खजाना

शहर से लेकर गांवों तक सड़कों का जाल बिछेगा। हर जिले की 5-5 महत्वपूर्ण सड़कों का विकास कराया जाएगा जिस पर 6500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्यारह सौ गांवों में 1505 करोड़ रुपए की लागत से कच्ची सड़कों पर डामर की सड़क बिछेगी तथा हर गांव में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक किलोमीटर लम्बाई में इंटरलॉकिंग टाइल का जाल बिछाया जाएगा। एलिवेटेड़ रोड के निर्माण से सुविधाएं बढ़ेंगी।

बजट में प्रदेश के 100 से ज्यादा शहरों में निकायों को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान दिया गया है। ड्रेनेज, सीवरेज और सौन्दर्यीकरण के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। शहर से गांवों तक हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के काम तेजी से होंगे। सस्ती बिजली के लिए नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। राज्य में एक नई बिजली कंपनी बनाए जाने का भी प्रस्ताव बजट में है। बजट में गरीबों के लिए सस्ते आवास बनाने के लिए भी पर्याप्त धन राशि स्वीकृत की गई है। 11,233 करोड़ रुपए परिवहन बेड़े को मजबूत करने पर खर्च किए जाएंगे। रोडवेज के बेड़े में भी 1,000 नई बसें शामिल होंगी। सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव सराहनीय है, इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

युवाओं का होगा सर्वांगीण विकास

बजट में मुख्यमंत्री ने अब युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति बनाने और इसके तहत 500 करोड़ रुपए के 'युवा विकास एवं कल्याण कोष' के गठन करने, भर्ती परीक्षाओं में आवेदन निःशुल्क करने व केवल एक बार फीस लेने, कई तरीकों से उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाने के वादे किए हैं।

इसके अलावा युवा उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू करने, स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने, विश्वकर्मा कामगार योजना के जरिए एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने जैसी बहुत सी घोषणाएं करने के साथ ही दिल खोल कर धनराशि का प्रावधान कर युवा मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया है।

औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख

बजट में औद्योगिक विकास की बुनियाद को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रदेश के 50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

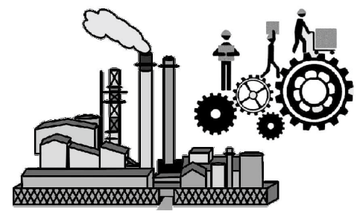

इकॉनोमिक जोन को विकसित करने पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उदयपुर में एयर कार्गो बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना का प्रस्ताव है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए सह कार्यस्थल बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना से अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। उद्यमियों का मानना है कि सरकार ने समग्र रूप से उद्योगों की गति को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया है।

बजट की अन्य राहतभरी खास घोषणाएं

खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ हर महीने मुफ्त फूड पैकेट भी दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

संविदाकर्मियों को किया जाएगा नियमित और आगे ठेके पर नियुक्ति होगी बंद। सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिलेगी पेंशन। मानदेय पर काम कर रहे कर्मियों और आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा 2-3 लाख रुपए का सहायता पैकेज।

आंगनबाड़ी बच्चों के लिए किया दो सेट यूनिफॉर्म देने का वादा। बुजुर्गों की पेंशन की राशि 500 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए करने का प्रस्ताव। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष का होने पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव।

निगरानी

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर